



वर्ष : 13 , अंक : 34, पृष्ठ : 08, नई दिल्ली सोमवार 21 अगस्त 2023, मूल्य : 1.50/-

नई दिल्ली से प्रकाशित

RNI No .DELHIN/2011/38334

मुख्य अपडेट

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रोहिणी से किया छठवें वन महोत्सव का शुभारंभ

.... पेज 03

14 जनपदों में 101 से अधिक व कुल 65 जनपदों ने 100 फीसदी पौधरोपण अभियान का लक्ष्य

.... पेज 05

पाकिस्तान के मैच तटस्थ देश में होते तो कार्यक्रम न बदलना पड़ता: सेठी

.... पेज 07

मणिपुर पुलिस ने 20 केस सीबीआई को सौंपे

इंफाल। मणिपुर पुलिस ने 20 केस सीबीआई को सौंपे हैं। इनमें दो मामले प्रमुख हैं, पहला- 7 साल के बच्चे को उसकी मां और आंटी समेत एंबुलेंस में जला दिया गया था। दूसरा- एक मैटैड महिला ने आरोप लगाया था कि 3 मई को कुकी नेताओं ने उसके साथ रेप किया था।

एक मामले की दो अलग-अलग एफआईआर

तोशिग हेंगसिंग (7) को उसकी मां मीना हेंगसिंग और आंटी लीडिया लॉरेनबाम इंफाल के अस्पताल ले जा रही थीं। तोशिग को सिर में गोली लगी



थी। बच्चे की मां मैटैड थी और पिता कुकी है। वेस्ट इंफाल में 4 जून को भीड़ ने उनकी एंबुलेंस को आग लगा दी। जबकि सुरक्षा में पुलिस चल रही थी। इस मामले में सीबीआई को दो

एफआईआर सौंपी गई हैं। लाम्फेल में एक एफआईआर पुलिस की तरफ से कराई गई, दूसरी कांगपोकपी में बच्चे के पिता जोशुआ हेंगसिंग ने दर्ज कराई। लाम्फेल में एफआईआर में हत्या की

मैटैड महिला का कुकी नेताओं पर रेप का आरोप

धारा लगाई गई, जबकि कांगपोकपी की एफआईआर में गैर इरादतन हत्या करने बात लिखी गई, जो मर्डर की श्रेणी में नहीं आता।

कांगपोकपी में दो दिन से महिलाओं का प्रदर्शन

मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार (18 अगस्त) को थोवाई कुकी गांव पर हमला हुआ था, जिसमें कुकी समुदाय के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले के विरोध में कांगपोकपी में दो दिन से महिलाओं

का प्रदर्शन जारी है। ये महिलाएं एनएच-2 पर पोस्टर लेकर बैठी हैं। इनकी मांग है कि पहाड़ी इलाकों में बीएसएफ और असम राइफल्स को तैनात किया जाए। इन लोगों ने विवादों में रहे सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को दोबारा लागू करने की मांग भी की है। इंफाल में 7 विधानसभा के कुल 19 पुलिस स्टेशनों को AFSPA से बाहर रखा गया है, जो हिंसा से जुड़ा रहे इलाकों में सेना को व्यापक शक्तियां देता है।



बंदर अखास में क्षेत्रीय देशों के साथ सहकारी समुद्री जुड़ाव की दिशा में भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में ईरान की यात्रा के दौरान आईएनएस त्रिकंद।

गंगोत्री हाईवे पर हादसा, 8 की मौत

बस 50 मीटर गहरी खाई में गिरी; 27 का रेस्क्यू



सीएम ने हादसे पर दुख जताया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा- हादसे में कुछ लोगों की जान जाने और कुछ के घायल होने की खबर मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ईश्वर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा को शांति दे। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।

गंगोत्री। उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी के पास रविवार (20 अगस्त) शाम को एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। 27 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 10 की हालत गंभीर है। बस में 32-33

पैसेजर्स सवार थे। उत्तरकाशी के डीएम और एस्पपी ने बताया कि बस नंबर यूके07पीके-8585 50 मीटर गहरी खाई में गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बस में गुजरात के लोग सवार थे। ये

गंगोत्री धाम की यात्रा करके लौट रहे थे। गंगनानी के पास ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया। इससे बस क्रेन बैरियर को तोड़ते हुए 50 मीटर गहरी खाई में लुढ़कने के बाद पेड़ों के बीच जाकर अटक गई।

ईडी के डर से नेताओं ने पार्टी छोड़ी : पवार

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि श्रद्ध हमारी पार्टी के कुछ लोगों की जांच कर रही थी। जिससे बचने के लिए कुछ दिनों पहले उन्होंने अजित पवार के साथ बीजेपी से हाथ मिला लिया। सरकार में शामिल होने के बाद वे कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दों पर बीजेपी के साथ आए हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे जांच का सामना नहीं करना चाहते थे। उन्हें भाजपा की ओर से कहा गया था कि आप अगर हमारे साथ आते हैं तो आपको जेल में कुछ नहीं होगा, नहीं तो आपको जेल में डाल देंगे। इस दौरान शरद पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख का जिक्र किया। एनसीपी चीफ ने कहा कि उन्हें भी बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन देशमुख ने जेल जाना स्वीकार किया और वहां 14 महीने बिताए। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, इसलिए अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी।

सीवीसी की रिपोर्ट में खुलासा : एमएचए रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें



नई दिल्ली। पिछले साल (2022) भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय और इसके बाद रेलवे और बैंकों में काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आई। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुल मिलाकर 1,15,203 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 85,437 का निपटारा कर दिया गया और 29,766 लंबित थे, जिनमें से 22,034 मामले तीन महीने से ज्यादा समय से लंबित थे। एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने शिकायतों की जांच करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सतर्कता अधिकारी शिकायतों की

जांच करने के लिए ईमानदार प्रहरी की दूरस्थ शाखा के रूप में कार्य करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल गृह मंत्रालय को अपने कर्मचारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिलीं, जबकि रेलवे को 10,580 और बैंकों को 8,129 शिकायतें मिलीं। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटारा कर दिया गया और 22,724 लंबित थीं, जिनमें से 19,198 तीन महीने से अधिक समय तक लंबित थीं। रिपोर्ट को हाल ही में सार्वजनिक किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है

रिपोर्ट में कहा गया है कि 4,710 शिकायतें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सहित), दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्तान प्रॉफेब लिमिटेड, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, एनबीसीसी और एनसीआर योजना बोर्ड के कर्मचारियों के खिलाफ थीं। इनमें से 3,889 का निपटारा कर दिया गया और 821 लंबित रहीं, जिनमें से 577 तीन महीने से अधिक समय तक लंबित रहीं। सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 4,304 शिकायतें कोयला मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ थीं, जिनमें से 4,050 का निपटारा किया गया, 4,236 शिकायतें श्रम मंत्रालय के खिलाफ थीं, जिनमें से 4,016 का निपटारा किया गया और 2,617 शिकायतें पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ थीं, जिनमें से 2,409 का निपटारा किया गया।

ड्रोन से की जाएगी मनरेगा में होने वाले कामों की निगरानी

नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कार्यों की निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए एक नई नीति तैयार की है। ड्रोन की मदद से जारी कामों की निगरानी, पूरे हो चुके काम की जांच, काम का आकलन और शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। हालांकि, केंद्र सरकार इन ड्रोनों के

लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त फंड नहीं देगी, बल्कि राज्यों को मनरेगा के लिए दी जाने वाली राशि में से आकस्मिक खर्च के लिए होने वाले आवंटन से ही ड्रोन के लिए राशि तय की जाएगी। ग्रामीण मंत्रालय ने कहा कि मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। इनमें मजदूरों के स्थान पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाना और बिना काम किए कुछ लोगों को वेतन मिलना शामिल हैं। ऐसे



मामलों में ड्रोन सुबूत जुटाने में मददगार होंगे। वहीं, ड्रोन का इस्तेमाल लोकपाल करेगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तैयार की एसओपी

लोकपाल तैनात किया जाएगा, जो स्वतःसंज्ञान लेकर शिकायतों को दर्ज करके उन्हें 30 दिनों के भीतर निपटाएगा। मंत्रालय ने अपने एसओपी में निर्देश दिया है कि इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन में उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा होना चाहिए। ऑफिशियल रूप से तेज हवाओं से बचने का भी सुझाव दिया गया है।

ड्रोन को कम से कम 30 मिनट तक हवा में रहने में सक्षम होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि ड्रोन के माध्यम से लिए गए सभी वीडियो और तस्वीरों को आनलाइन प्रणाली नरेगा साफ्ट के साथ साझा किया जाना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन के लिए डेटा का संग्रह किया जाना चाहिए।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यसमिति का किया गठन

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की बहुप्रतीक्षित सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति का गठन कर दिया है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने आज यहां बताया कि समिति में 39 सदस्यों के साथ ही 18 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 14 प्रभारी, नौ विशेष आमंत्रित सदस्य तथा चार पार्टी की विभिन्न संगठनों की अध्यक्ष शामिल हैं जिन्हें



पदेन सदस्य के रूप में कार्यसमिति में जगह दी गई है। उन्होंने बताया कि समिति में 39 प्रमुख सदस्य हैं जिनमें श्री खड़गे के अलावा पार्टी की पूर्व

अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एके अट्टोनी, आधारी रंजन चौधरी शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव के अनुसार समिति के अन्य सदस्यों में अंबिका सोनी, मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम, तारीक अनवर, लाल थनवला, अशोक चौहाण, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, चरणजीत सिंह चन्नी, प्रियंका गांधी वाड़ा, अजय

माकन, कुमारी सेलजा, गैंगनाम, एन रघुवीर रेड्डी, शशि थरूर, ताम्रध्वज साहू, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, दीपक बाबरिया, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह, जगदीश ठाकुर, जीए.पी.ए. अविनाश पांडे, दीपा दाम मुंशी, के.सी. वेणुगोपाल, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और कमलेश्वर पटेल शामिल हैं।

नूंह हिंसा को लेकर जंतर-मंतर पर महापंचायत

महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के भाषण पर बवाल; पुलिस ने लगाई रोक, जबरन ले गई

नई दिल्ली। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली स्थित जंतर-मंतर में आयोजित महापंचायत में बवाल हो गया। इस महापंचायत में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने भड़काऊ भाषण दिया। इस पर दिल्ली पुलिस ने एहतियातन महापंचायत को रोक दिया। साथ ही नरसिंहानंद को जबरन पंचायत से ले गई। इस दौरान उन्हें पुलिस ने मीडिया से भी बात नहीं करने दी।

नूंह में न हों कोर्ट ट्रायल

दिल्ली में जंतर मंतर पर पंचायत में पलवल, नूंह, गुरग्राम, रेवाड़ी, दिल्ली, रोहतक, झरनूर व अन्य क्षेत्रों से लोग भाग लेने पहुंचे। इस दौरान लोगों को नूंह जिले की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। जैन समाज नूंह के प्रधान विपिन जैन ने कहा कि यदि हालात यही रहे तो एक दिन नूंह कश्मीर में बदल जाएगा। उन्होंने मांग की कि दंगों में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके कोर्ट ट्रायल गुरग्राम अथवा अन्य जिलों की अदालतों में कराए जाएं। नूंह जिले की अदालतों में पीड़ित बयान नहीं दे पाएंगे।

मरने वाले लोगों को सरकार द्वारा मुआवजा देने की मांग की। साथ ही वहां रहने वाले हिंदू समाज की सुरक्षा को लेकर चिंता प्रकट की। सरकार से कहा गया है कि मेवात में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दिल्ली पुलिस की ओर से किसी अप्रिय घटना की

आशंका को देखते हुए पंचायत के चारों ओर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया। इससे पहले हरियाणा में भी पंचायतें हो चुकी हैं। जिसमें यह तय किया गया था कि हरियाणा के बाद दिल्ली में नूंह हिंसा में मारे गए लोगों और उनके परिजनों को न्याय की आवाज उठनी चाहिए थी।

यह महापंचायत ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन ने बुलाई थी। जिसमें हरियाणा के गोरक्षक मोनू मानेसर और बिट्टू बजगी पर चर्चा की गई। इधर दिल्ली पुलिस ने इस पंचायत की वीडियोग्राफी कराई। पंचायत में वक्तवाओं ने हिंसा में

ट्रिपल मर्डर पति ने भी सुसाइड किया; कुते को मारने से मना किया तो परिवार पर हमला कर दिया

उज्जैन में पत्नी, बेटा-बेटी की तलवार से काटकर हत्या



तलवार लेकर कुते को मारने के लिए दौड़ा। पत्नी गंगा पवार ने समझाया तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी।



बीच-बचाव करने पर बेटी नेहा (17), फिर बेटे योगेंद्र (14) को भी तलवार से हमला कर मार डाला घर

में मौजूद दो और बच्चों (बेटा-बेटी) छत पर भागे और वहां से कूदकर जान बचाई। बाद में दिलीप ने भी तलवार से अपना गला काटकर खुदकुशी कर ली। जिदा बचा बेटा बोला, सट्टा खेलते थे पिता

आरोपी पेशे से किसान था। अस्पताल में भर्ती दिलीप के बेटे तपेंद्र ने बताया कि पिता शराब पीते थे और सट्टा भी खेलते थे। बेटे डिलीप ने बताया कि पिता शराब के नशे में थे और हमें मारने के लिए तलवार लेकर दौड़े। चिड़चिड़ाकर परिवार पर हमला किया

उज्जैन स्क्वैड्रन शर्मा ने बताया कि दंपती में झगड़ा कुते के भोंकने के कारण हो रहा था। उसने कुते पर हमला किया, लेकिन परिवार के हस्तक्षेप करने से वह चिड़चिड़ा गया। इस कारण उसने बीवी-बच्चों पर हमला कर दिया।

संपादकीय



पहाड़ों पर ये कैसी आपदा

कभी जम्मू-कश्मीर तो कभी हिमाचल प्रदेश और कभी उत्तराखण्ड में देवी आपदाओं की होड़ लगी है। ये आपदाएं प्रकृति की नाराजगी के स्पष्ट संकेत हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि अपने ही वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की चेतावनियों को अनदेखीं की जा रही है, जिसका दुष्परिणाम हम जोशीमठ और शिमला में देख रहे हैं। इससे पहले प्रकृति का रौद्र रूप हम 2013 में केदारनाथ में देख चुके हैं। अमरनाथ में भी 1996 और 2012 में देख चुके हैं। नैनीताल में सन् 1880 में आए भूस्खलन में 151 लोगों के कानग्रस्त होने का इतिहास हम नहीं भूलें हैं। अब वहां बनियांजाला लोगों को बेचैन कर रहा है। भूस्खलन की जो भयावह तस्वीर शिमला की नजर आई वैसी ही आशंका पहाड़ों की रानी मसुरी में भी नजर आ रही है।

सन् 1864 में जब अंग्रेजों ने जाक्यू पर्वत पर अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी तो उसकी आबादी मात्र कुछ सैकड़ों में थी। आजादी के बाद हुई जनगणना में वहां की आबादी 46,150 दर्ज हुई जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य घोषित होने पर 1971 में 56,032 हो गई। अब तक की नवीनतम 2011 की जनगणना में वहां की जनसंख्या 1,69,578 हो गई। सन् 2011 में मात्र 36 वर्ग किमी में फैले शिमला शहर का जनसंख्या घनत्व 4,800 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो चुका था।

शिमला नगर निगम के रिकार्ड के अनुसार इस छोटे से क्षेत्रफल में 32 वार्ड और 46,306 घर हैं। फिलहाल हमारे सामने शिमला से भी ज्वलंत उदाहरण बन कर सामने आ गया था। इसरो और रिमोट सेंसिंग ऐजेंसी द्वारा इसी साल फरवरी में भूस्खनन की दृष्टि से भारत के जिन 147 जिलों का एटलस जारी किया है उनमें 108 जिले केवल हिमालयी राज्यों के हैं जिनमें सभी 13 जिले उत्तराखण्ड के तथा हिमाचल प्रदेश के 12 में से 10 जिले हैं। इसी तरह जम्मू-कश्मीर के भी 8 जिले संवेदनशील जिलों की सूची में इसरो ने शामिल किए हैं। संवेदनशीलता की दृष्टि से शिमला जिला 61 वें नम्बर पर है। जबकि उससे कहीं अधिक संवेदनशील मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, चम्बा और किन्नोर जिले हैं। जब ये स्थिति हम शिमला की देख रहे होते हैं तो उसी हिमाचल के बाकी संवेदनशील जिलों पर मंडरते खतरे की कल्पना की जा सकती है।

इसरो और रिमोट सेंसिंग के नवीनतम भूस्खलन संवेदनशीलता एटलस पर गौर करें तो उत्तराखण्ड की स्थिति बेहद चिन्ताजनक नजर आती है। भूस्खलन की दृष्टि से देश के सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले हैं, जिन्हें नम्बर एक और दो पर रखा गया है। सन् 1998 में केदारघाटी के मनसूना और गोंडार क्षेत्र में कई गांव विखर गए थे। उसी साल 18 अगस्त को पिथौरागढ़ के मालपा में हुए भूस्खलन में प्रौतिमा बेदी समेत लगभग 200 मानसरोवर यात्री और अन्य लोग मारे गए थे।

शिमला और जोशीमठ भविष्य के लिए प्रकृति की गंभीर चेतावनी है। इन दो नगरों की ही जैसी बाकी पहाड़ी नगरों की कहानी है। आर्थिक गतिविधियों के कारण पर्यटन, तीर्थटन के महत्व के छोट से कस्बों में आस पास के गावों की जनसंख्या आकर्षित होने लगी और ये कस्बे धीरे-धीरे नगरों में बदलने लगे। प्रशासनिक दृष्टि से ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों में जन सुविधाओं और आर्थिक कारणों से जनसंख्या बढ़ने लगी तो ये छोट कस्बे भी नगर और महानगर बनने लगे।

बैंक शुल्क सुधार

बैंकों द्वारा किसी भी वसूली को न्यायसंगत बनाने की कोई भी कोशिश सराहनीय है। वैसे तो बैंकों को स्वयं ही न्यायपूर्ण ढंग से काम करना चाहिए और जहां भी दंडात्मक शुल्क लगाने की जरूरत है, वहां तार्किकता से काम लेना चाहिए, पर आम तौर पर बैंक ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को आवश्यक निर्देश जारी करना पड़ा है। ऋण पर दंडात्मक शुल्क और ब्याज दरों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का यह कदम कारगर सिद्ध होना चाहिए। ऋण खातों में दंड शुल्क के संबंध में ये दिशा-निर्देश 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होंगे। हालांकि, अगर कोई वसूली गलत ढंग से या गलत मानसिकता के साथ की जा रही है, तो उसे जल्द से जल्द रोकने में कोई हर्ज नहीं है। पहली जनवरी 2024 तक न जाने कितने ग्राहकों से करोड़ों रुपये बैंक गलत ढंग से वसूल लेंगे। ऐसे जरूरी आर्थिक सुधारों को जल्द से जल्द लागू करने के प्रति उदासीनता ठीक नहीं है। अपने हित में कोई नया शुल्क वसूलने में बैंक जब देरी नहीं करते हैं, तब ग्राहकों के हित में किसी शुल्क सुधार के लिए उन्हें इतना समय क्यों मिलना चाहिए? भारतीय रिजर्व बैंक ने फेयर लौंडिंग प्रैक्टिस संबंधी अपनी ताजा अधिसूचना में बताया है कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत ऋण देने वाले संस्थानों को ब्याज की दंडात्मक दरें लगाने के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नति लागू करने की स्वायत्तता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर ऋण न चुका पाए, तो उस पर कितना दंड लगाया है, इसका निर्धारण बैंक अपने स्तर पर ही करेगा है। कोई बैंक ज्यादा दंड लगाता है और कोई कम लगाता है, लेकिन ज्यादातर बैंक ऋण न चुका पाने पर बहुत आक्रामक ढंग से व्यवहार करने के साथ ही भारी दंड वसूली के पक्ष में रहते हैं। अनेक बैंक तो लगाए गए आर्थिक दंड पर भी ब्याज वसूलते हैं। ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्ति दंड पर दंड भुगतान चला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक दंड वसूली के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह चाहता है कि बैंक जायज रूप से वसूली करें। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवाच्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना पैदा करना है और ऐसे शुल्कों का उपयोग ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। झड़ुदिसा-निर्देश तो यह भी है कि बैंक ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं करेंगे। बैंकों को अपने बोर्ड के स्तर पर नीति बनानी पड़ेगी। दंडात्मक शुल्क की मात्रा न्यायोचित होगी। व्यक्तिगत उधार और गैर-व्यक्तिगत उधार के लिए होने वाली शुल्क या दंड वसूली में समानता होगी। यह आम तौर पर देखा जाता है कि बैंक निजी या व्यक्तिगत या पर्सनल लोन के मामले में बहुत सख्त होते हैं, जबकि ऋण लेने वाले उद्योगपतियों या कंपनियों के प्रति उनका रवैया अपेक्षाकृत बहुत उदार होता है। ऋण न चुका पाने वाली कंपनियों के मामले में तो बैंक दंड, ब्याज और कई बार मूल ऋण राशि में भी भारी कमी कर देते हैं। मतलब, भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा दिशा-निर्देश से आम लोगों या व्यक्तिगत कर्जदारों के साथ न्याय की तलाज दिशा-निर्देश से आम लोगों या व्यक्तिगत कर्जदारों के साथ न्याय की तलाजाना बढ़ सकती है। यह बात जाहिर है कि बैंक सामान्य ऋणों से नाना प्रकार की वसूली करते हैं और अनेक जाहिर तौर तो मूलभूत सेवा में भी कमी बरतते हुए ग्राहकों को नुकसान पहुंचाते हैं। बैंकों को आम ग्राहकों के अनुरूप पूरी तरह बदलने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है।



सुरक्षा बलों में बढ़ता टकराव गहन चिंता का विषय



तनवीर जाफ़री

मणिपुर गत सौ दिनों से भी अधिक समय से हिंसा की आग में झुलस रहा है। हिंसक वारदातों के इस लंबे दौर में हत्याएं, बलात्कार, महिलाओं की नजर परेड, घर व बस्तियां जलाने, बड़ी संख्या में धर्मस्थलों को जलाने जैसी तमाम दुर्भाग्यपूर्ण अपराधिक घटनायें हो चुकी हैं। परन्तु इन सबसे भयावह वारदातें मणिपुर में उन पुलिस व सुरक्षाबलों का विभाजित हो जाना व उनपर पक्षपाती होने का आरोप लगना, जिनपर राज्य में हिंसा को रोकने का ज़िम्मा है। माना जा रहा है कि यदि सुरक्षा बलों में धार्मिक व जातीय आधार पर विभाजन न हुआ होता तो तो राज्य में इतना खून खराबा हुआ होता न ही इतनी हिंसक वारदातें हुई होतीं। मणिपुर से इस तरह की खबरें हिंसा भड़कने के पहले दौर से ही आनी शुरू हो गयी थीं कि मैतेयी व कुकी समुदाय से सम्बन्ध रखने वाले राज्य पुलिस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा अपने अपने समुदाय के लोगों को सरकारी हथियार बांटे गये। तो कहीं शह पाये हुए इन्हीं उपद्रवियों द्वारा थाणों व शस्त्रागारों से हथियार लूट लिये गये। जाहिर है जब उपद्रवियों के हाथों में संगीन सरकारी शस्त्र हों और स्वजातीय पुलिस कर्मियों का भी खुला साथ हो तो हिंसा के तांडव को भला राज्य की कौन से मशीनों रोक सकती है? परन्तु जब जब देश के किसी भी राज्य

जीवन में स्पृहा, लोभ और लालच दिशाहीनता और विचलन के बड़े कारक

यदि मनुष्य के बाद बहुत सारा धन है उसमें से कुछ दान करता है तो यह बढूपन नहीं होगा अपितु यदि किसी के पास थोड़ी धन संपदा हो और वह उसमें से काफी कुछ अति जरूरतमंद लोगों को दान करता है तो यह मानवीय जीवन का श्रेष्ठ पहलू होगा। [जियो और जीने दो तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना जिस मनुष्य समाज और देश में बलवती हो उस समाज की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है और वह समाज साधुधाम का पात्र होगा।मनुष्य में उसाह है जोवन जीने की जिजीविषा होनी चाहिए। जीवन में आकस्मिकत परिवर्तनशीलता और निरंतर विकास की संभावनाओं की तलाश होती रहनी चाहिए। जो मनुष्य जीवन मानव जाति एवं समाज के समग्र कल्याण के लिए जीता है वह जीवन को सार्थकता की ओर अग्रसर करता है। शास्त्रों में

सर्पों की पूजा और उनका संसार



सुरेश सिंह बैस 'शाव्रत'

नागपंचमी का त्यौहार भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम पूर्वक मनाया जाता है। इस दिन गांवों और शहरों में कुश्ती ,दंगल के खेल अखाड़ों में आयोजित किये जाते हैं। विलासपुर शहर में गोडुपारा स्थित मसूलाल अखाड़ा समिति द्वारा प्रतिवर्ष लालबहादुर शास्त्री स्कुल के मैदान में दंगल प्रतियर्था का आयोजन किया जाता है। गांव गांव में इस अवसर पर लोगों द्वारा नागपूजा की जाती हैं एवं नागों को दूध लाई खेतों एवं देवालयों में पिलाया एवं चढ़ाया जाता है। नागपंचमी का दिन अनेकानेक मंत्रों की सिद्धि के लिये बाबा गुनियाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वैदिक धर्म में नागपंचमी मानने की कई प्रचलित, कथाएं हैं। फिर भी मंत्र साधना हेतु इस दिवस का विशेष महत्व होता है बैगा गुनिया लोग इस तिथि को पहली तिथिवार से यानी चौथ से लगा हुआ मानकर रात अपने शिष्यों को गुरुमंत्र देने की तैयारी में लगे रहते हैं मुख्यतः इस दिन को मंत्र सिद्धि

मणिपुर पुलिस VS असम राइफल्स



का प्रशासनिक कार्य केंद्रीय गृह मंत्रालय देखाता है जबकि इसका परिचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। असम राइफल्स के प्रशिक्षण के अनुरूप इसे पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों तथा भारत-म्यांमार सीमा पर तैनात किया गया है। पूर्वोत्तर में पूर्व में भी होने वाली हिंसा या उथल पुथल को नियंत्रित करने में असम राइफल्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसे देश के सबसे अच्छे सैन्य सुरक्षा संगठनों में एक माना जाता है।

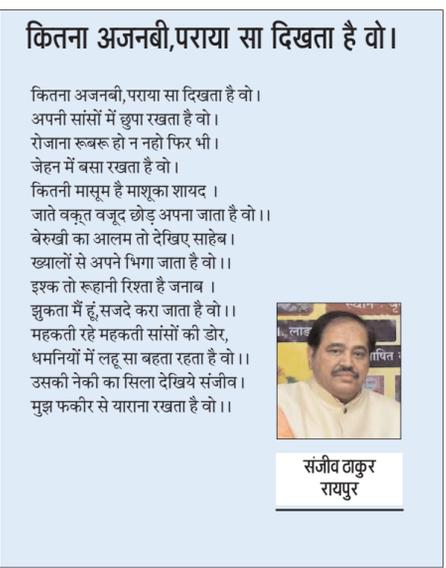
यही असम राइफल्स पूर्वोत्तर के अशांत राज्य मणिपुर में भी विगत कई वर्षों से तैनात है। प्रशिक्षण के मुताबिक़ इसे मणिपुर के कई क्षेत्रों विशेषकर पर्वतीय इलाकों व म्यांमार से लगती सीमा के क्षेत्रों में तैनात किया गया है। उधर मणिपुर पुलिस पक्षपात के आरोपों का सामना कर रही है। कुकी समुदाय का भरोसा मणिपुर पुलिस से पूरी तरह उठ गया है वहीं असम राइफल्स के ऊपर यह समुदाय भरोसा जता रहा है। ठीक इसके विपरीत मैतेयी समुदाय के लोग यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक विधायक व नेता भी मणिपुर के कई अशांत क्षेत्रों में असम राइफल्स की तैनाती का विरोध कर रहे हैं। गौर तलब है कि मणिपुर की कुल आबादी में मैतेई लोगों की तादाद

नई दिल्ली सोमवार 21 अगस्त 2023 Www.gauravshalibharat.com

मणिपुर पुलिस VS असम राइफल्स

यह भी कहा गया है कि असम राइफल्स नियष्कता बनाये रखने में असफल रही और जनता ये आरोप लगा रही है कि उनको भूमिका पक्षपातपूर्ण है जिसमें वो एक समुदाय का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल चूंकि असम राइफल्स की तैनाती लंबे समय से प्राय: पहाड़ी और सीमा से लगते इलाक़े में है और यही कुकी बाहुल्य वाले इलाक़े भी हैं। इसी आधार पर कुकी और असम राइफल्स के बीच घनिष्ठता का आरोप मैतेई समुदाय द्वारा लगाया जा रहा है।

ठीक इसके विपरीत कुकी समुदाय के भी दस विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मणिपुर से असम राइफल्स को न हटाने की अपील की है। कुकी विधायकों ने कहा है की यदि असम राइफल्स को यहां से हटाय़ा गया तो राज्य में कुकी व अन्य आदिवासी समुदाय की सुरक्षा ख़तरे में पड़ जाएगी। असम राइफल्स को मणिपुर से हटाने की भाजपाइयों की मांग के बीच अब यह भी सुनाई देने लगा है कि मणिपुर हिंसा कथित रूप से सीमा पर यानी म्यांमार से प्रभावित है। इस तरह की खबरें असम राइफल्स देश के संघीय प्रतिष्ठता तथा पुलिस व सुरक्षा बलों के दृढिबत अविश्वास से चिंतनीय भी है और यह शुभ संकेत भी नहीं है।



कितना अजनबी,पराया सा दिखता है वो।

कितना अजनबी,पराया सा दिखता है वो। अपनी सांसों में छुपा रखता है वो।रोजाना रूबरू हो न नहो फिर भी। कितनी बसा रखता है वो। जेहन में मासूम है मासूका शायद।जाते वक़्त वजूद छोड़ अपना जाता है वो।। बेरखी का आलम तो देखिए साहेब।इखालों से अपने भिगा जाता है वो।।

श्कल तो रूहानी रिरता है जनाब।

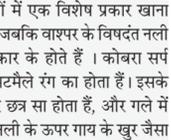
शुकता में हूँ,सजदे करा जाता है वो।।

महकती रहे महकती सांसों की डोर,

धमनियाँ में लहू सा बहता रहता है वो।।

उसको नेकी का सिला देखिये संजीव।

मुझ फकीर से याराना रखता है वो।।



संजीव ठाकुर रायपुर

मैं तो जहर होता ही नहीं। कम जहर वाले सांप के काटने से नशा पर हो सकता है। बिना जहर वाले सांप का काटना और कांटा चुभना एक बराबर हैं। संसार का सबसे जहरीला सांप हैं आस्ट्रेलिया का टाइगर स्लेक, किंग कोबरा भी भयंकर जहरीला होता हैं। जितनी तेजी से सांप का जहर असर करता हैं, उससे भी अधिक तेजी से मनुष्य के मनोमस्तिफ़ पर असर करता हैं सांप काटने का भय। अक्सर मृत्यु की वजह जहर और भय दोनों ही होते हैं। हमारे देश में केवल दो सौ से तीन सौ जहरीले सांप पाये जाते हैं। इनमें कोबरा, करैत, सास्केल, वाइपर और रसेल्स वाइपर आदि चार जातियां सर्वाधिक जहरीली होती हैं। इन चारों जातियों के सांपों का जहर मनुष्य को तो छोड़िये हाथी तक को मार डालने में सक्षम होता हैं। परम, कालगण्डेस, संखचूड़, भदा, शेभनाग, कालीनाग, राजनाग, तामेश्वरी, फूलफंगार, ऐराज, प्रहलाद, डीडू, धामिन, रक्तवंशी, अजगर,सुआमंफ़ी, जलेबिया और दुमई आदि सांपों की लगभग पचास जातियां ऐसी हैं, जिनके सांप जहरीले कम लेकिन ज्यादा खतरनाक होते हैं। सांप उण्डेदेशों में कम पाये जाते हैं और गर्म देशों में अधिक पाये जाते हैं। यही कारण है कि भारत, अफ़्रीका, थाइलैंड और श्रीलंका में सांप अधिक होते हैं।

कम अधिक की बात छोड दे तो संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है

अदृय जिजीविषा के साथ संघर्ष में विजयी होने की कामना भी होनी चाहिए। मनुष्य के जीने की स्वच्छंद प्रवृति केवल मनुष्य को आनंद एवं आम संतोष प्रदान कर सकती है पर ईश्वर के बनाए मनुष्य की परिणति सर्वथा इसके विपरीत है, मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील होकर मानवीय संवेदनाओं को सहेज कर जगत के कल्याण के बारे में तन मन धन से प्रयास करना चाहिए तथा मनुष्य के जीने का लक्ष्य संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है।विभिन्न चिंतकों का मानना है कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब अलग-अलग किर्दार की तरह उसे निभाते चल जाते हैं। पर इस किर्दार की निभाने में सच्चाई अमरदार प्रयत्नशीलता एवं संघर्षों के प्रति साहस जिंदगी को रुचिकर बनाकर आगे बढ़ने के प्रयास को द्विगुणित करते हैं।

मणिपुर पुलिस VS असम राइफल्स

अनुभव ही हमारे फूकें,मोर गुरु के फूकें ।।

गुरु कोमो महादेव पार्वती के फूकें।पेट पीरा उड़िया जा ।।

उक्त मंत्र पढ़कर ही सिद्ध, नहीं किया जा सकता है।मंत्र साधना के पीछे कुछ बंदिशें भी रहती हैं अगर बंदिशों का उल्लंघन कर कोई, लोगों को ठगकर पैसा कमाने का उपाय करेगा तो उसक मंत्र शक्तिक्षण हो जाती हैं यह मान्यता भी सर्वमान्य है। यह भी कहा जाता है कि अगर शिष्य गुरु को अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेता हैं तो कठिन से कठिन मंत्र भी वह स्वपतित कर अनपढ़ गंवार शिष्य को भी मंत्र प्रदान कर देता हैं। किसी मंत्र के लिये संस्कृत ज्ञान का होना जरुरी नहीं होता। शायद उक्त छत्तीसगढ़ी बोली में प्रस्तुत मंत्र को पढ़कर सहेज हो में कोई विश्वास नहीं कर पायेगा फिर भी इस अंचल की लाखों ग्रामीण जनता की यही मान्यता और विश्वास का हस्तांतर साल दर साल नागपंचमी के अवसर पर होता आला है।यदि इस दिन कोई बैगा किसी कारण वश मंत्रों को शिष्यों में प्रसार नहीं कर पाता तो वह आने वाले भादो महीने के ऋषि पंचमी के पहले दिन लिये अनेकशिष्यों को मंत्रों से जगंरगत करता है। एक अन्य क्रिया नामन की होती हैं इसकी प्रक्रिया वृद्धि रुपाकार में होती हैं इसमें नागपूजा के पन्धरे दिन गांव के बाहर किसी मैदान को साफ सुथरा बनाकर उसे दलदली बना दिया जाता है, दूसरे दिन यानी पंचमी को सार्वजनिक रूप से शिष्यों को बुलाकर

^[1] मणिपुर पुलिस VS असम राइफल्स

